भारत की कूटनीति के लिए रोहिंग्या चुनौती

साभार : लाइव मिंट

(13 सितंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

म्यांमार में रखाइन राज्य से अनुमानित 300,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों ने दो सप्ताह के अन्दर पड़ोसी बांग्लादेश में शरण ले लिया है। यह अफरातफरी 25 अगस्त को आतंकवादी समूह अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) द्वारा किये गये हमले के बाद शुरू हुई थी, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गवां दी थी। पिछले हफ्ते तक, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार की यात्रा पर थे, तब नई दिल्ली ने सादे तौर पर कथित आतंकवादी हमले की निंदा की और सुरक्षा की कमी और शरणार्थी स्थिति के बारे में बात करने से बचने की कोशिश करता रहा। भारत की स्थिति नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की की सरकार के लिए राहत भरी थी, जिन्हें रोहिंग्या के मुद्दे से निपटने के लिए व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि भारत ने अब अपना रुख थोड़ा बदल दिया है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उसने म्यांमार के आचरण की पहली आलोचना क्यों नहीं की। इसका पहला कारण यह है कि म्यांमार उत्तर भारत के पूर्व राज्यों में उग्रवाद के खतरों से निपटने में मदद करता है। दूसरा, म्यांमार भारत के अधिनियम पूर्व नीति की सफलता की कुंजी है। तीसरा, म्यांमार की एक सार्वजनिक निंदा करने से इसके चीन के करीब पहुंचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। म्यांमार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बीजिंग के वीटो पर निर्भर है, इसलिए रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा वहां तक पहुंच जायेगा। चौथा, भारत भी 25 अगस्त को एआरएसए द्वारा आतंकवादी हमलों में लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूहों की संभावित भूमिका से अवगत है। यहाँ कुछ रिपोर्ट है जिन्होंने कुछ सुझाव पेश किया है कि दोनों भारत और बांग्लादेश ने म्यांमार के पश्चिमी राज्य में रोहिंग्या और अन्य जातीय समूहों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने पर कोफी अन्नान की अगुवाई वाली रखाइन सलाहकार आयोग की रिपोर्ट जारी करने के साथ संभव आतंकवादी हमलों के म्यांमार को अवगत कराया जाना चाहिए।

देखा जाये तो शरणार्थियों का यह झुंड बांग्लादेश में तब प्रवेश कर रहा है, जब देश बाढ़ से जूझ रहा है और नरेंद्र मोदी के म्यांमार के दौरे के दौरान पेश किये रुख से निराश है, इसलिए बांग्लादेश ने आखिरकार अपनी नाराजगी को जताने का फैसला किया। हांलाकि, अब भारत ने अपनी स्थिति को संशोधित करने और शरणार्थियों के बहिर्वाह से संबंधित चिंताओं को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 9 सितंबर के बयान में आंग सान सू की की सरकार को पहले कारण बताए गए कारणों की निंदा करने से रोकता है।

हांलाकि, म्यांमार की तरह ही बांग्लादेश भी भारत के प्रति-उग्रवाद प्रयासों और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शरणार्थियों की भारी भीड़ ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को घरेलू झटका देने का मौका दे दिया है, जिसे वहां के विपक्षी दल भारत की तरफ झुकना मानते हैं। एक असहाय भारतीय दृष्टिकोण बांग्लादेश में हसीना की स्थिति को कमजोर बना देगा और अपने प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया को मजबूत करेगा, जो हमेशा से भारत विरोधी माना जाता है। पाकिस्तान की कपटी और भारत-विरोधी खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) के साथ-साथ जिया की बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी और जमात-ए-इस्लामी हसीना के प्रतिद्वंदी रहे हैं। साथ ही एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 अगस्त को हुए आतंकवादी हमलों का लक्ष्य बांग्लादेश में जिया की स्थिति को हसीना की कीमत पर बढ़ावा देना है। वैसे भी यह ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने वाला है।

भारत अभी एक कठिन दुविधा में फंसा हुआ है, क्योंकि भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के विरोधाभासी हितों को संतुलित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि शरणार्थियों के हमले के बारे में चिंतित होने के इसके अपने स्वयं के कारण हैं। भारत को पता है कि कई रोहिंग्या भी इसके क्षेत्र में आयेंगे। यह इस समूह के कट्टरता से डरता है और पहले ही भारतीय मंत्रियों ने कुछ 40,000 अवैध रोहिंग्या आप्रवासियों के निर्वासन के लिए कुछ बयानों का ब्योरा मांगा है।

25 अगस्त के आतंकवादी हमलों के लिए म्यांमार की प्रतिक्रिया सभी के लिए चिंता का विषय है। हांलाकि, यह पहली बार नहीं है कि भारत 'गुमराह' शासन के बीच पड़ोस में समस्याओं को पनपते देख रहा है या इस क्षेत्र में अधिक से अधिक चीनी सहभागिता को मजबूतीपूर्ण रणनीति अपनाकर आमंत्रित कर रहा है। यह दुविधा केवल इसलिए भी बढ़ी है, क्योंकि चीन इसमें अधिक दिलचस्पी ले रहा है और उसकी नजर हमेशा से इन क्षेत्रों पर है। अतीत में, भारत पड़ोसी देशों को शामिल करता आया है और कथित मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सार्वजनिक व्याख्यान देने के पश्चिमी दृष्टिकोण का अनुसरण करने की

बजाय शांत कूटनीति के माध्यम से अपने व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश की है। भारत के तरीके, भले ही अधिक प्रभावी है, फिर भी यहाँ अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है।

समस्या का हल म्यांमार में ही है। म्यांमार के साथ आतंकवाद के सहयोग के संबंध में जब भारत अपना ध्यान नहीं रख सकता है, तो यह एक साथ शरणार्थियों के बहिर्वाह को दूर करने के द्वारा किया जाना चाहिए। एनान की अगुवाई वाली आयोग की रिपोर्ट कहती है कि म्यांमार के नागरिकता कानून, 1982 के तहत रोहिंग्या को नागरिकता से छीन लिया गया है, इसलिए यह इसके नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया के लिए बहस करती है, साथ ही यह रोहिंग्या की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ उपयोगी सुझावों की पेशकश कर सकते हैं। बांग्लादेश और भारत वास्तव में कुछ शरणार्थियों को आश्रय दे सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि दोनों देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभावों के परिणामस्वरूप बोझ के रूप में सामना करना पड़ेगा।

भारत को कसौटी पर चलना पड़ सकता है। एक तरफ, म्यांमार को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद करते रहना है तो दूसरी तरफ शरणार्थियों के प्रवाह को शामिल करने और बांग्लादेश और भारत में पहले से ही शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के लिए जमीन की स्थिति बनाने के लिए काम करना है। भारत को सार्वजनिक बयान के द्वारा बांग्लादेश को इस प्रक्रिया के माध्यम से आश्वस्त किया जाना चाहिए। वर्ष 2018 के चुनावों में भारत के असहनीय दृष्टिकोण की धारणा, जिया के लिए एक अवसर बन सकता है जिससे निश्चित तौर पर नुकसान भारत को होगा।

इससे संबंधित तथ्य

म्यांमार की चीन पर बढ़ती निर्भरता

- चीन के साथ म्यांमार के रिश्ते इसलिये महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इन सबंधों के केंद्र में म्यांमार के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है।
- विदित हो कि चीन म्यांमार में एक 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' का निर्माण करने के लिये रियायतें दे रहा है। साथ ही, म्यांमार के क्यूक्यूऊ (Kyaukpyu) में एक प्राकृतिक एवं गहरे समुद्री बंदरगाह के विकास में भी चीन की दिलचस्पी है जो कि उसकी 'रोड एंड बेल्ट परियोजना' का हिस्सा बन सकता है।
- गौरतलब है कि चीन द्वारा म्यांमार में समय-समय पर सशस्त्र जातीय संघर्षों के तेज होने के दौरान विद्रोही समूहों और म्यांमार सरकार के बीच शांति वार्ता कराने में मध्यस्थ की भूमिका अदा की जाती है।
- इसके अलावा, रखाइन राज्य में जारी संघर्ष में म्यांमार को मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए, संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब उस पर सवाल उठाया जाएगा तो वह अपने हितों के संरक्षण के लिए चीन पर ही निर्भर रहेगा, क्योंकि 'वीटो पावर' चीन को प्राप्त है न कि भारत को।

भारत से अपेक्षित प्रयास

- यदि भारत को म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करना है तो उसे भारत-म्यांमार आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना होगा। वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 2.2 अरब डॉलर का है, जिसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है।
- 'कालादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' और 'भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग' जैसी परियोजनाओं को गति देनी होगी।
- मांडले स्थित 'म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी' जैसी और भी मानव विकास परियोनाएँ आरम्भ की जानी चाहियें। हालाँकि ऐसी संभावना है कि यात्रा के दौरान नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं या विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर सहयोग की घोषणा की जा सकती है।

और अधिक प्रयास की जरूरत क्यों?

- वर्ष 2022 तक कालादान और 'भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग' जैसी परियोजनाओं के समुचित कार्यान्वयन से भारत को महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा, लेकिन दुर्भाग्य से वाणिज्यिक व्यापार और निवेश के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भारत का म्यांमार में निवेश आधार काफी संकीर्ण है।
- म्यांमार से कृषि एवं वन उत्पाद और तेल व गैस को वह विस्तारण देना होगा जो म्यांमार की विकासीय की जरूरतों के साथ-साथ 3 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पूरा कर सके।
- भारत और म्यांमार बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय सहयोग की वह रूपरेखा तय करनी होगी जो दोनों ही देशों के लिये लाभप्रद हो।

संभावित प्रश्न

म्यांमार के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए भारत को अपने दृष्टिकोण में बदलाव और धैर्य लाने की आवश्यकता है। वर्तमान में जारी रोहिंग्या समस्या के संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट करें। (200 शब्द)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322